

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 71/14

GCMS NO 2014/00221

1. कल्याण उर्फ रामकल्याण पुत्र अर्जुन
2. सुरझानी पत्नि कल्याण जातियान गुर्जर निवासीयान विलोली नदी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांत

बनाम

- राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारना डूंगर
- श्री. रमणारायण पुत्र रामजीलाल गुर्जर निवासी विलोली नदी तहसील मलारना डूंगर
3. भम्बल पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी विलोली नदी तहसील मलारना डूंगर

रेसपो

(अपील विरुद्ध मु0नं0 46/12 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.14 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूंगर )


अभिभाषक अपीला0 श्री सत्येन्द्र कुमार गौयल  
अभिभाषक रेसपो 2 की और से पैरोकार सरकार  
रेसपो 2 व 3 की और से कोई उपस्थित नहीं

दिनांक 21.10.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णयव डिक्री दिनांक 31.10.14 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूंगर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेसपो0संख्या 1/वादी तहसीलदार द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0न0 763 रकबा 0.29 है0 सम्पूर्ण ग्राम बाढ विलोली मे अपीलांत व रेसपो0संख्या 2 व 3 द्वारा अवैध रूप से बजरी संग्रहण कार्य मे उपयोग किया जा रहा है जो धारा 177 आर टी एक्ट के तहत अवैधानिक है खातेदार द्वारा यह अवैधानिक कार्य किया जा रहा है। खातेदारी अपनी कृषि भूमि मे केवल कृषि कार्य ही कर सकता है, परन्तु खातेदार द्वारा भूमि का संपरिवर्तन कराये बिना राज्य सरकार की अनुमति के बिना बजरी संग्रहण कार्य किया जा रहा है। जो अवैधानिक है। जो अवैधानिक है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्त भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर




वादी/तहसीलदार का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या 2 व 3 वावजूद तामिल के उपस्थित नहीं हुए। बहस अपीलांट अधिवक्ता एवं सरकार पैराकार की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह अपीलांट को वादी व उसके गवाहान से जिरह करने का मौका देती लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने वादी व उसके गवाहान को जिरह करने का मौका दिये बिना वादी को गवाह का मुख्य परीक्षण कराकर साक्ष्य पूर्ण कर ली जो विधि के सिद्धान्त व नेचूरल जस्टिस के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए था। अपीलांट आराजी ख0न0 763 रकबा 0.29 है0 के खातेदार काश्तकार है। अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग काश्त के लिए करता है। अपीलांट द्वारा अपनी भूमि पर कभी बजरी का संग्रहण नहीं किया है। गवाह ने भी वर्तमान में बजरी का कोई संग्रहण कार्य नहीं करना स्वीकार किया है। आराजी ख0न0 763 रकबा 0.29 है0 के संबंध में गवाह धर्मसिंह गुर्जर द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं की। रिपोर्ट कर्ता गवाह के रूप में उपस्थित नहीं हुआ है। बिना रिपोर्ट कर्ता की साक्ष्य के अदालत मातहत ने अपीलांट को बजरी संग्रहण कर्ता मानकर भूल की है। आराजीयात ख0न0 763 में बजरी संग्रहण होने की कोई गिरदावरी भी नहीं है। धारा 177 के तहत अपीलांटान की खातेदारी समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

जबाब में पैरोकार सरकार ने कथन किया अपीलांट द्वारा अवैध रूप से बजरी के संग्रहण करने के कारण ही पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.8.12 को बजरी के संग्रहण किये जाने की रिपोर्ट पेश की गई है जो पटवारी हल्का चक बिलोली धर्म सिंह पुत्र नादान सिंह गुर्जर के बयान दिनांक 24.7.14 से स्पष्ट है। जिसके आधार पर वादी/तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पेश किया गया है। तत्पश्चात अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 व 3 को मौके से बेदखल करने किये जाने या इस संबंध में जबाब प्रस्तुत करने के नोटिस अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 4.10.12 को नोटिस जारी किये गये हैं। जिसमें अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से जरिये अधिवक्ता जबाब पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई है। अपीलांट/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में साक्ष्य नहीं कराने हेतु मना किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की गई है। मौके पर अवैध संग्रहण अपीलांट द्वारा किये जाने पर वादी/तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में भूमि को रिसिवरी में लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने रिसिवर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमि पर तहसीलदार का वाद के निस्तारण तक रिसिवरी में लेने के आदेश प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ किये

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर


के कारण ही अपीलधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि अनुरूप है। अतः अपीलांत की भील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि भूमि खोल 763 रकबा 0.29 है 0 ग्राम बाढ़ बिलोली तहसील मलारना डूंगर पर अपीलांत व रेस्पों संख्या 2 व 3 द्वारा अवैध रूप से बिना किसी सक्षम स्वीकृति के बजरी का खनन करने के कारण ही पटवारी हल्का द्वारा उनके विरुद्ध रिपोर्ट तहसील कार्यालय मलारना डूंगर में की गई है। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ही तहसीलदार/वादी द्वारा अपीलांत व रेस्पों संख्या 2 व 3 के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पेश किया गया है। वाद पत्र पेश करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी द्वारा वेदखल एवं वाद पत्र में जबाब पेश करने बाबत नोटिस जारी किया गया था। जिसमें अपीलांत व रेस्पों संख्या 2 व 3 के द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब पेश किया गया था। अपीलांत का कथन रहा कि प्रकरण में रिपोर्टकर्ता के बयान दर्ज नहीं किये गये हैं जबकि अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का धर्म सिंह गुर्जर के बयान पत्रावली में संलग्न है। अपीलांत का कथन रहा कि अपीलांत को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 21.10.14 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य कराने से मना करने के उपरान्त ही साक्ष्य बंद की गई है। अपीलांत द्वारा विवादित आराजीयात पर बजरी के संग्रहण नहीं करने बाबत किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र ना तो इस न्यायालय में पेश किया है ना ही अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है इससे स्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के भूमि पर बजरी का संग्रहण किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियमों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही अपीलधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांत की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर के मु०नं० 46/12 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.14 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



  
(लक्ष्मी कांत बालोत)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर